

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा मण्डल



y  
19-6-12

- 1. राजकुमार, तनय हुरु कुम्हार साठ ओवरी तहसील देवसर जिला सिंगरौली मण्डल
- 2. रामलाल

आवेदकगण

R. 2022-112

बनाम

मण्डल शासन

अनावेदक

अधिवक्ता श्री जी.पी. शर्मा  
द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दि. 31.5.2012  
मा न्यवर 31.5.12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील  
देवसर प्र. क्र. 189/अ6अ/11-12 आदेश दि. 0  
13.4.12

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50म. प्र. भू. रा. सं.

निम्नांकित आधारों पर निगरानी पेश है:-

॥ 1॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है।

॥ 2॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मूल अभिलेख तलब कराये ही पट्टा फर्जी मानकर निरस्त करने में कानूनी भूल की है।

॥ 3॥ यह कि ग्राम ओवरी की आ. नं. 2003/2 रकबा 1.00 हे. का पट्टा

तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र बरगवां तहसील देवसर जिला सीधी के द्वारा आवेदक गण के नाम प्र. क्र. 631/अ19४४/91-92 आदेश दिनांक 30.7.12 के द्वारा किया गया

जिसमें तहसीलदार देवसर द्वारा अपने समक्ष अधिकारी के आदेश को बिना पुनर्विलो की स्विकृत के खसरा सुधार के माध्यम से निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो काबिल निरस्तगी है।

॥ 4॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा दिनांक 30.3.12 को दिनांक 13.4.12 को पेशी दी गई व दिनांक 13.4.12 को पेशी पर दिनांक 20.4.12 पेशी दी गई थी तथा दिनांक 24.4.12 को पेशी पर बताया गया कि दिनांक 30.3.12 को ही आदेश ही गया है विरुद्ध नवल केडर निगरानी समय सीमा के अंदर है।

1689  
दिनांक 19.6.12

UD

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

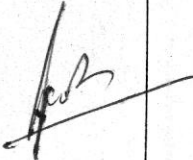
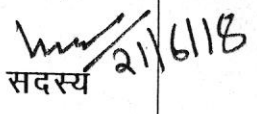
--

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी - 2022-एक/2012

जिला-सिंगरौली

राजकुमार कुम्हार विरुद्ध शासन(म0प्र0)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एम.के. अग्निहोत्री उपस्थित हुये, उन्हें कायमी पर सुना गया ।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया । तहसीलदार देवसर के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि पर आवेदक की फर्जी प्रविष्टी को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश दिया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती। अतः प्रकरण में ग्राह्य के पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>  सदस्य 21/6/18</p>